दीपावली में पेंशनरों का डीआर बढ़ाया

4.5 लाख से अधिक पेंशनरों को होगा फायदा

170 करोड़ का भार पड़ेगा सरकार के खजाने पर

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 14 अक्टूबर. राज्य सरकार ने प्रदेश के पेंशनरों को दीपावली से पहले सौगात देते हुए महंगाई राहत बढ़ा दिया है.

सातवें वेतानवान वाले पेंशनरों का डीआर जहां 2 फीसदी बढ़ाया गया है, वहीं छठवें वेतनमान वाले पेंशनरों का डीआर 6 फीसदी बढ़ाया गया है. ये डीआर एक सितंबर से प्रभावी किया गया है, जिसका भुगतान अक्टूबर के डीआर में किया जाएगा. राज्य सरकार के इस निर्णय से मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार के खजाने पर 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इसी के साथ प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत मिल गई है. वर्तमान में सातवें वेतनमान वाले पेंशनरों को 53 फीसदी डीआर दिया जा रहा था, जो कि अब बढ़कार 55 फीसदी हो जाएगा. वहीं छठवें वेतनमान वाले पेंशनरों को 246 फीसदी डीआर देय था, जो अब बढ़कर 252 फीसदी हो जाएगा. वित्त विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र भेजा था, छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 25 अगस्त को राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दी थी. राज्य सरकार पहली बार कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों के किसानों से कोदो-कुटकी उपार्जन करेगी.

> खरीफ वर्ष 2025 में प्रदेश के सोयाबीन के किसानों को लाभांवित किये जाने के लिए भारत सरकार की प्राईज डिफिसिट पेमेन्ट स्कीम लागू की गयी है, जो प्रदेश में भावांतर योजना कहलायेगी. प्रदेश में सोयाबीन भावांतर योजना के तहत 24 अक्टूबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक सोयाबीन का विक्रय, राज्य की अधिसूचित मंडियों में किया जायेगा. प्रदेश की मंडियों में 14 दिवस के सोयाबीन के विक्रय मूल्य के औसत के आधार पर सोयाबीन के मॉडल रेट की गणना की जायेगी.

योजनाओं को समयावधि में पूर्ण करें

रीवा जिले की नल-जल योजनाओं की समीक्षा की

भोपाल, 14 अक्टूबर. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में रीवा जिले की नल-जल प्रदाय योजनाओं की वृहद् समीक्षा की.

उन्होंने निर्माणाधीन नल-जल योजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने तथा क्रियान्वित योजनाओं के विधिवत संचालन एवं संधारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी. नरहरि, एमडी मध्यप्रदेश जल निगम के वीएस चौधरी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कदैला समूह जल प्रदाय योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने टमस एवं बाणसागर समूह जल प्रदाय योजनाओं की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी और निर्देश दिए कि इनटेक वेल, डब्ल्यूटीपी, एमबीआर तथा जेडएमबीआर से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है.

> उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ जल का सीधा स्वास्थ्य लाभ है. सुरक्षित और प्रदूषण रहित जल से जलजनित रोगों, जैसे पेचिश, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी. उन्होंने अधिकारियों से निर्देश दिए कि जल शुद्धिकरण प्रक्रियाओं और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि हर ग्रामवासी को स्वास्थ्यकर और स्वच्छ जल उपलब्ध हो.

अवैध भंडारित किए लाखों के पटाखे जब्त

मुरैना. जिले में पुलिस प्रशासन ने पटाखों के अवैध भंडारण और विक्रय के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में करीब तीन लाख रुपए से अधिक के अवैध पटाखे जब्त किए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार यह अभियान पिछले वर्ष दो स्थानों पर हुए पटाखा विस्फोटों में आधा दर्जन लोगों की मौत और कई मकान धराशाई होने के कारण एहतियात के तौर पर चलाया जा रहा है. पुलिस के अनुसार उन लोगों के घरों पर भी कड़ी निगरानी और तलाशी की जा रही है, जिनके घरों पर पिछले वर्ष पुलिस को छापे के दौरान अवैध पटाखों का भंडारण मिला था.

छिंदवाड़ा में लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई

छिंदवाड़ा. पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश पर जबलपुर लोकायुक्त इकाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जिला सहकारी बैंक, तामिया में एक ट्रेप अभियान चलाया. इसमें आदिम जाति एवं सेवा सहकारिता समिति झिरपा के प्रभारी समिति प्रबंधक मुनीम प्रसाद पटेल को 59,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा. आवेदक हरीश राय, जिला छिंदवाड़ा, का वेयरहाउस श्री हरि नाम से संचालित है. शिकायत के अनुसार, आरोपी मुनीम प्रसाद पटेल ने वेयरहाउस के सुचारू संचालन और ब्लैकलिस्ट में न डालने के एवज में रिश्वत की मांग की थी.

सड़क धंसने से उजागर हुआ भ्रष्टाचार

भोपाल-इंदौर बायपास सड़क धंसने की घटना लापरवाही का उदाहरण

विशेष संवाददाता

भोपाल. मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि भोपाल-इंदौर बायपास (बिलखिरिया एवं सूखी सेवनिया) पर सड़क धंसने की हालिया घटना भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण है.

करीब 305 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस सड़क का लगभग 100 मीटर हिस्सा धंस गया, जिससे 20 से 30 फीट गहरा गड्ढा बन गया. सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन पटवारी ने कहा कि यह किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि संयोग का परिणाम है. उन्होंने याद दिलाया कि जुलाई 2025 में एमपी नगर की मुख्य सड़क पर भी इसी तरह की धंसान हुई थी, जिससे राजधानी की सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे.

12 साल में इस सड़क से 650 करोड़ टोल वसूला

पटवारी ने कहा, कुछ ही महीनों में दो बड़ी सड़कें धंसना इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम पूरी तरह सड़ चुका है. 12 साल पुरानी इस सड़क से अब तक 650 करोड़ से अधिक टोल वसूला गया है, फिर भी रखरखाव पर एक पैसा खर्च नहीं किया गया. ग्रामीणों की बार-बार की शिकायतों के बावजूद सड़क के नीचे पानी भरने की समस्या को अनदेखा किया गया. 2020 में मेंटेनेंस अनुबंध समाप्त हो गया, पर निगरानी नहीं हुई. यह भ्रष्ट तंत्र और '50 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार' का नतीजा है.

सिंघार ने जातिवादी व धार्मिक उन्माद पर जताई गहरी चिंता

भोपाल, 14 अक्टूबर . मध्यप्रदेश में हो रही जातिवादी और धार्मिक उन्माद से जुड़ी घटनाओं पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गहरी चिंता व्यक्त की है.

उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि प्रदेश में हाल ही में दमोह में हुई जातिवादी घटना, ग्वालियर में अनिल मिश्रा का विवादित बयान और भोपाल की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर समाज में समानता के बजाय विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं. उमंग सिंघार ने कहा, इन घटनाओं ने मुझे भीतर तक विचलित कर दिया है. यह देश बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके बनाए संविधान से चलेगा, न कि भाजपा और आरएसएस की व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से. उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी देश के संविधान की रक्षा के लिए समर्पित हैं. नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जाए.

सोनोग्राफी सेवाओं के लिए 87 मेडिकल ऑफिसर हुए अधिकृत

भोपाल, 14 अक्टूबर. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि 11 वर्षों के सतत् विभागीय प्रयासों और समर्पित कार्य के बाद पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत कम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट के परिणाम घोषित किए गए हैं.

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा घोषित परिणामों में 87 चिकित्सक ने सफलता प्राप्त की है। अब ये सभी पात्र चिकित्सक सोनोग्राफी के क्षेत्र में वैध रूप से चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान कर सकेंगे. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी. प्रशिक्षित एवं प्रमाणित चिकित्सक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अल्ट्रासाउंड सेवाएं उपलब्ध कराकर गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच सेवाओं को सशक्त करेंगे. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सफल हुए सभी चिकित्सकों को बधाई देते हुए उनसे अपेक्षा की कि वे इस उपलब्धि को समाजसेवा का माध्यम बनाते हुए प्रदेश के प्रत्येक कोने में सेवा की भावना से कार्य करें.

आयोजन | भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अरुण सिंह ने कहा

गुजरात यूनिट में जल्द बनेंगे सेमीकंडक्टर

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 14 अक्टूबर. कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक शासन करने के बाद भी देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन के बारे में नहीं सोचा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश में छह सेमीकंडक्टर उत्पादन यूनिट लग रही हैं और जल्द ही गुजरात में स्थापित यूनिट से उत्पादन भी शुरू हो जाएगा. प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का आह्वान किया था और मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारा यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है. विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. यह बात मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अरुण सिंह ने कही. अरूण सिंह आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक भी है. यहां उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत बैठक को संबोधित किया.

> इसी क्रम में 150यूनिटी मार्च को लेकर कार्यशाला में हिस्सा लिया. बाद में उन्होंने समन्वय भवन में अभियान के तहत दक्षिण-पश्चिम विधान सभा के सम्मेलन को संबोधित किया. इससे पहले पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने विकास के मामले में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारों ने शासन किया. उन सरकारों ने सीमेंट, लोहा, औद्योगिक उपकरण जैसे अनेक बड़े क्षेत्रों को सरकार के लिए रिजर्व कर दिया.